भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5340
25.03.2026 को उत्तर देने के लिए

पैमाना पोर्टल और प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का प्रबंधन

5340. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री पी. सी. मोहनः
डॉ. भोला सिंहः
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकिः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः
श्री विजय बघेलः
श्री नलिन सोरेनः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्री अभिमन्यु सेठीः
श्री रोडमल नागरः
श्री बिभु प्रसाद तराईः
श्री राजकुमार चाहरः
श्री जुगल किशोरः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा रही 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य की जारी अवसंरचना परियोजनाओं की विशेषकर राजस्थान और झारखंड में संख्या कितनी है;

(ख) राष्ट्र निर्माण के लिए परियोजना मूल्यांकन, अवसंरचना निगरानी और विश्लेषण (पैमाना) वेब-पोर्टल की शुरुआत से केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में विलंब और लागत वृद्धि की तात्कालिक निगरानी में किस प्रकार सुधार हुआ है;

(ग) क्या सरकार किसी परियोजना के अपनी मूल स्वीकृत लागत से 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाने पर प्रशासनिक मंत्रालयों को विशिष्ट सिफारिशें प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विलंबित परियोजनाओं के लिए अंतर-मंत्रालयी बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) के साथ समन्वय करने के लिए उपयोग की जाने वाली व्यवस्था का विशेषकर झारखंड और जम्मू-कश्मीर में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कर्नाटक में विलंबित या लागत वृद्धि का सामना करने वाली प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या कितनी है और किए गए सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क),(ख) और (ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां. और कार्य. कार्यां. मंत्रा.) को 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाली चल रही केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति की निगरानी करने का अधिदेश है, और यह कार्य पैमाना (राष्ट्र निर्माण के लिए परियोजना मूल्यांकन अवसंरचना निगरानी और विश्लेषण) नामक एक नई वेब निगरानी प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है।

जनवरी 2026 तक की स्थिति के अनुसार, पैमाना 17 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही 1,702 राष्ट्रव्यापी चालू परियोजनाओं की स्थिति को दर्ज करता है, जिनकी मूल लागत ₹33.71 लाख करोड़ और संचयी व्यय ₹20.01 लाख करोड़ है। इन परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा https://ipm.mospi.gov.in/ पर उपलब्ध फ्लैश रिपोर्ट में देखा जा सकता है।

तदनुसार, सभी चालू अवसंरचना परियोजनाओं और राजस्थान, झारखंड, जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक राज्यों से संबंधित परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा इस मंत्रालय द्वारा वेबसाइट https://ipm.mospi.gov.in/ReportPage पर प्रकाशित फ्लैश रिपोर्ट में उपलब्ध है।

"एक डेटा एक प्रविष्टि" के सिद्धांत के अनुरूप, पैमाना पोर्टल को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के एकीकृत परियोजना निगरानी पोर्टल (आईपीएमपी) के साथ केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा को स्वचालित रूप से प्राप्त करने में सक्षम एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से एकीकृत किया गया है। एकीकृत मंच, पैमाना से मैन्युअल प्रविष्टि को काफी हद तक कमी हुई है, जिसमें सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कोयला मंत्रालय से संबंधित लगभग 64 प्रतिशत परियोजनाएं स्वचालित रूप से अपडेट हो रही हैं।

(ग) और (घ): सभी हितधारकों (अवसंरचना संबंधी मंत्रालय/विभाग) को भी पैमाना पर उपलब्ध डेटा विश्लेषण के आधार पर उनकी परियोजना के कार्यान्वयन और उसमें हुए विलंब के संबंध में नियमित रूप से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे अपनी ओर से परियोजना कार्यान्वयन के प्रबंधन में आवश्यक हस्तक्षेप

कर सकें। इसके अतिरिक्त, मासिक समीक्षा बैठकों और अन्य संचार माध्यमों से हितधारकों के साथ नियमित समन्वय साक्ष्य-आधारित निगरानी में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, अनुकूलित डैशबोर्ड तक पहुंच प्रदान करने वाले लॉगिन क्रेडेंशियल पहले ही सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा कर दिए गए हैं, जिससे उन्हें परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए पोर्टल तक सीधी पहुंच प्राप्त हो जाती है।

भारत सरकार द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं में विलंब को कम करने और उनमें तेजी लाने के लिए उठाए गए अन्य प्रमुख कदमों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगति बैठकों के तहत परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा और सख्त परियोजना मूल्यांकन शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) का परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) एक संस्थागत तंत्र है जिसे परियोजनाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर आधारित निगरानी करने और अंतर-मंत्रालयी/राज्य समन्वय के माध्यम से 500 करोड़ रुपये और उससे अधिक के अनुमानित निवेश वाली परियोजनाओं के लिए मुद्दों के समाधान में तेजी लाने तथा अनुमोदन/मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित प्रगति बैठकों के अतिरिक्त, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) डीपीआईआईटी और मंत्रिमंडल सचिवालय स्तर पर विलंब/समस्याओं का सामना कर रही परियोजनाओं की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। इन समीक्षाओं को प्रभावी बनाने के लिए, पीएमजी ने एक अद्वितीय 5-स्तरीय, वर्धन (एस्केलेशन) रूपरेखा लागू की है जो यह सुनिश्चित करता है कि मुद्दों का उचित स्तर पर समाधान किया जाए, जिसमें नियमित मुद्दों के लिए संबंधित मंत्रालय से शुरुआत होती है और जटिल मुद्दों के लिए प्रगति तक बात पहुंचती है। यह दृष्टिकोण समीक्षा तंत्र को सुव्यवस्थित करता है, दोहराव को रोकता है, और उच्च अधिकारियों को उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है जिनमें उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

*****